



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 3 दिसम्बर, 2009 / 12 अग्रहायण, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 27th November, 2009

No. HPERC/SECY/609/B-III/PC/JSR/RV-3426-28/2009.—The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission in exercise of the powers conferred by subregulation(5) of regulation 3 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) Regulations, 2004 hereby makes the following Order to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of the Appointment of Electricity Ombudsman) Order, 2004 namely :—

1. Short Title .—This Order may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Appointment of the Electricity Ombudsman) (First Amendment) Order, 2009.

2. Amendment of Para 7.—In Para 7 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of the Appointment of Electricity Ombudsman) Order, 2004, for “Rs. 22,400-525-24,500”, “Rs. 67,000-79000 (annual increment @ 3%) w.e.f. 1st January, 2006” shall be deemed to have been substituted.

By order,
Sd/-
Secretary.

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 24 दिसम्बर, 2009

संख्या सिंचाई 11-3/2008-शिमला.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रवृत्ति होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव बगैण, तहसील ठियोग जिला शिमला में उठाऊ पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला, जिला शिमला को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र/हैक्टर में
शिमला	ठियोग	बगैण	283	0-08-30

शिमला-171002, 30 नवम्बर, 2009

संख्या सिंचाई 11-31/2009-शिमला.—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव गजैड़ी उठाऊ पेयजल योजना जैस बासा ठियोग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित है, हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश

करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र/हैक्टेयर
शिमला	ठियोग	गजैड़ी	674	0 14 51
			675	0 14 54
		Kittas	2	0 29 05

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला—171002, 25 नवम्बर, 2009

संख्या पी0बी0डब्ल्यू(बी)एफ(5) 10/2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव सहलोन, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में नम्होल-बहादरपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वाक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	क्षेत्र बीघा—बिस्वा
बिलासपुर	सदर	सहलोन	34 / 1	2—4
			35 / 1	1—6
			36 / 2	0—5
			48 / 38 / 2	1—17
			40 / 1	1—13
			41 / 1	0—8
			42 / 1	0—16
			कुल जोड़ किता	7

शिमला—171002, 25 नवम्बर, 2009

संख्या पी०बी०डब्ल्यू(बी)एफ(5) 11/2009.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव टेपरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में नम्होल—बहादरपुर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि—अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा—4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वाक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू—अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	क्षेत्र बीघा—बिस्वा
बिलासपुर	सदर	टेपरा	330 / 240 / 1	0—3
			331 / 240 / 1	0—2
			331 / 240 / 2	4—12
			348 / 251 / 3 / 2	2—15
			270 / 2	3—4
			275 / 1	0—11
			कुल जोड़ किता	6

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव।

शहरी विकास विभाग**अधिसूचना**

शिमला, 25 अक्टूबर, 2009

संख्या यू0 डी0-ए (1) 3/2007.—नगर पंचायत नगरोटा बगवां, बददी, घुमारवीं, मनाली, और रोहडू की प्रास्थिति (हैसियत) को नगर परिषद घोषित करने के प्रस्ताव को, इस विभाग की समसंख्या अधिसूचना तारीख 11-06-2007 और 04-10-2007 द्वारा, उक्त नगर पंचायतों के प्रभावित व्यक्तियों से उपायुक्त कांगड़ा, सोलन, बिलासपुर, कुल्लू, शिमला और निदेशक, शहरी विकास के माध्यम से तीस दिनों के भीतर आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 16-01-2008, 02-07-2007 और 05-10-2007 में प्रकाशित किया गया था ;

उपायुक्त कांगड़ा, सोलन, बिलासपुर, कुल्लू, शिमला और निदेशक, शहरी विकास द्वारा किसी भी प्रभावित व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

और निदेशक, शहरी विकास और उपायुक्त कांगड़ा, सोलन, बिलासपुर, कुल्लू तथा शिमला ने उक्त घोषणा को अन्तिम रूप देने की सिफारिश की है ;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत नगरोटा बगवां, बददी, घुमारवीं, मनाली, और रोहडू को तुरन्त प्रभाव से स्तरोन्नत करके नगर परिषद नगरोटा बगवां, बददी, घुमारवीं, मनाली, और रोहडू घोषित करती है और अनुसूची के भाग-II से क्रमशः क्रम संख्या-23, 31, 12, 28 व 7 पर प्रविष्टी का लोप करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 का भी संशोधन करती है और अनुसूची के भाग-I में क्रमशः क्रम संख्या 21, 22, 23, 24 व 25 का अन्तःस्थापन करती है ; अर्थातः—

क्रम संख्या

21. नगर परिषद नगरोटा बगवां
22. नगर परिषद बददी
23. नगर परिषद घुमारवीं
24. नगर परिषद मनाली
25. नगर परिषद रोहडू

उपरोक्त नगर पंचायतों नामतः नगर पंचायत नगरोटा बगवां, बददी, घुमारवीं, मनाली, और रोहडू के नगर परिषदों में स्तरोन्नयन के परिणाम स्वरूप, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) की धारा 305(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सचिव, नगर पंचायतों के सचिवों के 05 पदों को इन नगर परिषदों के कार्यकारी अधिकारी में स्तरोन्नत करने के लिए सहर्ष आदेश देती हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

[Authoritative English text of this Department Notification No. UDA(1)3/2007 dated 25-11-2009 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25 Nov., 2009

No. UD-A(1)-3/2007.—Whereas, a proposal to declare the status of Nagar Panchayats of Nagrota Bagwan, Baddi, Ghumarwin, Manali and Rohru to that of Municipal Council notified vide this Departments' notifications of even number dated 11-06-2007 & 04-10-2007 was published in the Rajpatra, H.P. (Extra-ordinary) dated 16-01-2008, 02-07-2007 & 05-10-2007 for inviting objections from the affected persons of said Nagar Panchayats through Deputy Commissioners, Kangra, Solan, Bilaspur, Kullu, & Shimla and Director of Urban Development within 30 days;

And whereas, no objections have been received from any of the affected people by the Deputy Commissioners, Kangra, Solan, Bilaspur, Kullu, & Shimla and Director, Urban Development;

And whereas, the Director, Urban Development and Deputy Commissioners, Kangra, Solan, Bilaspur, Kullu, & Shimla have recommended finalization of the said declaration;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by second proviso to sub-section(2) of section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to upgrade the Nagar Panchayats of Nagrota Bagwan, Baddi, Ghumarwin, Manali and Rohru to that of Municipal Councils of Nagrota Bagwan, Baddi, Ghumarwin, Manali and Rohru and also to amend Schedule I of the said Act by deleting entries at Sr.No 23, 31, 12, 28, 7 respectively from part –II of the schedule and to insert them at Sr. No. 21, 22, 23, 24, 25 respectively in part-I of the schedule, namely:—

Sr. No.

21. Municipal Council Nagrota Bagwan,
22. Municipal Council Baddi,
23. Municipal Council Ghumarwin,
24. Municipal Council Manali
25. Municipal Council Rohru

Consequent upon upgradation of above mentioned NagarPanchayats namely - Nagrota Bagwan, Baddi, Ghumarwin, Manali and Rohru to that of Municipal Councils, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred by Section 305(1) of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), is pleased to upgrade five posts of Secretaries of Nagar Panchayats to that of Executive Officers, of these Municipal Councils.

By order

Sd/-

Addl. Chief Secretary.

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 23 नवम्बर, 2009

संख्या पब-ए-(3) 61/99.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में प्रकाश सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध “क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग प्रकाश सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या पब-ए.(3)28/87 तारीख 05-09-1988 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, लोक सम्पर्क (प्रकाश सहायक) अराजपत्रित (वर्ग-III) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 1988 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप-नियम 2 (1) के अधीन इस प्रकार निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
सचिव ।

उपाबन्ध-क

हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, में प्रकाश सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.— प्रकाश सहायक

2. पदों की संख्या.— 02 (दो)

3. वर्गीकरण.— वर्ग-III (अराजपत्रित)

4. वेतनमान.—(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.— 5000-160-5800-200-7000-220-8100 /—रूपये

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.—7500 /— रूपए प्रतिमास (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महगाई वेतन के बराबर होगी)

5. चयन पद अथवा अचन पद.— अचयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.— 18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्पूर्वी ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गये थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया जाता है, या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:—(क) अनिवार्य अर्हता(ए) :

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैट्रिक या इसके समतुल्य ।
- (ii) सिनेमाटोग्राफिक नियमों की सक्षमता के अधीन अनुज्ञप्ति अवश्य रखता हो; और
- (iii) मंच, फिल्मों या टेलीविजन में प्रकाश का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।

(ख) **वॉछनीय**—हिमाचल प्रदेश की रुढियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं:—आयु : लागू नहीं । **शैक्षिक अर्हताएं :** लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:— दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता:—यथास्थिति, शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सेकेडमैंट आधार पर दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और तथाकथित स्तम्भ में विनिदिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियाँ (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—प्रोजेक्टर ऑपरेटर/सिनेमा ऑपरेटर/ऑटो मकैनिक में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में से इस पद के समतुल्य वेतनमान के पदधारियों में से सेकेन्डमेंट आधार पर :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए समस्त पात्र कर्मचारियों की उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्गवार वरिष्ठता को छोड़े बिना, एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी जिसमें प्रोजेक्टर आप्रेटर(ज)/सिनेमा आप्रेटर(ज) को ऑटोमकैनिक से सामुहिक रूप से ऊपर रखा जाएगा :

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपयुक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे कनिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवाए जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोरसिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्निकल सर्विसिज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो । और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्निकल सर्विसिज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई नियमित लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि ऐसे पद पर तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु यह और भी कि उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना आवश्यक है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि, यथास्थिति, हिमाचल लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी :—

(1) सकल्पना:

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में प्रकाश सहायक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.**—निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में यथा विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियाँ.—संविदा के आधार पर नियुक्त प्रकाश सहायक को 7500/—रुपये की नियत समेकित संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो पश्चात् वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 160/—रुपये की रकम (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा पर नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7500/—रुपये की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 160/—रुपये (पद के वेतनमान के न्यूनतम प्रारम्भिक में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहवृद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवाएँ पूर्णतः अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को, किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्युटी) से अनुपस्थित की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में नुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ0 आर0-एस0आर0, छुटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथा वर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लांक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध 'ख'

प्रकाश सहायक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमतिपुत्र/पुत्री.....निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

‘द्वितीय पक्षकार’ ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रकाश सहायक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रकाश सहायक के रूप मेंसे प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्.....दिन को स्वयमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त प्रकाश सहायक, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त प्रकाश सहायक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त प्रकाश सहायक, कर्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी अधिकारी/कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ (जी0आई0एस0) के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1.-----

(नाम व पूरा पता)

2.-----

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1.-----

(नाम व पूरा पता)

2.-----

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

Annexure-A

[Authoritative English text of this Department Notification No. Pub-A (3)14/99 dated 23-11-2009 required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 23rd November, 2009

No.Pub.A-3(61) /99 .—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules, for the post of Lighting Assistant, Class-III (Non-Gazetted), in the Department of Information & Public Relations Himachal Pradesh, as per Annexure “A” attached to this notification, namely:—

1. *Short title and Commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Information and Public Relations Lighting Assistant, Class-III (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal & Savings.*— (1) The Himachal Pradesh Public Relations Department Lighting Assistant, (Public Relations), Non-Gazetted (Class-III) Recruitment and Promotion Rules, 1988 notified vide notification No. Pub_A(3)28/87 dated 05-09-1988, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
 Sd/-
 Secretary.

Recruitment and Promotion Rules for the post of Lighting Assistant, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Information & Public Relations, H.P.

1. **Name of the Post.**—Lighting Assistant
2. **Number of Post(s).**—02 (Two)
3. **Classification.**—Class-III (Non-Gazetted)
4. **Scale of Pay.**—(i) Pay Scale for regular incumbents:
Rs.5000-160-5800-200-7000-220-8100
(ii) Emoluments for Contract employees:
Rs.7500/- per month (which shall be equal to initial of pay scale + Dearness pay)
5. **Whether “Selection” Post or “Non-Selection” Post.**—Non-Selection
6. **Age for direct recruitment.**—Between 18 and 45 years’

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment.

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servant. This concession will not however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies who were/are finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchange or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. **Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.**— (a) **ESSENTIAL QUALIFICATION(S).**— (i) Matric or its equivalent from a recognized University / Board.

(ii) Must possess a licence under competency of Cinematographic Rules, and (iii) Should possess two years experience of lighting in Stage, Films or Television.

(b) **DESIRABLE QUALIFICATIONS.**— Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).— *Age.*—Not applicable.

Educational Qualification.—Not Applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment basis failing both by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Column No. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/ transfer is to be made.—By promotion from amongst Projector Operators / Cinema Operators / Auto Mechanic with 05 years regular service or regular combined with continuous adhoc service, rendered, if any, in the grade failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post and are in the identical pay scale from other H.P. Government Departments.

Provided that for the purpose of promotion a combined seniority list of all eligible officials will be prepared on the basis of their length of service without disturbing their cadre-wise inter-seniority in which the Projector Operator(s) / Cinema Operator(s) shall be placed en-block above the Auto Mechanics.

(i) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his / her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the Recruitment and Promotions Rules for the post, whichever is less,

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him / her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.— As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.— As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.— A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.— Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms & conditions given below:—

(I) **Concept.**—(a) Under this policy, the Lighting Assistant in the Department of Information & Public Relations H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.**—The Director Information & Public Relations, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) **Contractual Emoluments.**—The Lighting Assistant appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 7500/- per month (which shall be equal to initial of pay scale + Dearness pay). An amount of Rs. 160/- (equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) Appointing /Disciplinary Authority.— The Director, Information & Public Relations H.P. will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) Selection Process.— Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board.

(V) Committee for Selection of contractual appointments.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board from time to time.

(VI) Agreement.— After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) Terms & conditions.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs 7500/- per month (which shall be equal to initial of pay scale + Dearness pay). The Contract appointee will be entitled for annual increase in contractual amount @ Rs. 160/- (equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as seniority/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(h) Provision of service rules like FR-SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.— Not Applicable.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

Annexure-“B”

Form of contract/ agreement to be executed between Lighting Assistant and the Government of Himachal Pradesh through Director, Information & Public Relations, H.P.

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____ between Sh./Smt. _____ s/o/D/o Sh. _____ R/o _____

Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Director, I&PR Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Lighting Assistant on contract basis on the following terms & conditions:

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Lighting Assistant, for a period of 1 year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e on _____. And information notice shall not be necessary.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. _____ per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed / posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Lighting Assistant will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Lighting Assistant. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A Contractual Lighting Assistant will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant

beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.
9. The employee Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee (s).

IN WITNESS the FIRST PARTY And SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES :

1. _____

(Name and full address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____

(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESSES :

1. _____

(Name and full address)

2. _____

(Name and full address)

(Signature of the SECOND PARTY)

SPECIFIC NOTIFICATION

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 3rd December, 2009

No. Fin-2-C(5)-9/2008.---Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of **Rs. 200.00 crore** (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this

notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the revised General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003 dated 20th July, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the loan

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.
- (ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003, dated 20-7-2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price format.

Allotment to Non-Competitive Bidders

3. The Government Stock up to 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on **December 8, 2009**. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Negotiated Dealing System (NDS) as stated below on December 8, 2009.

- (a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Negotiated Dealing System(NDS) between 10.30 A.M. and 12.30 P.M.
- (b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Negotiated Dealing System (NDS) between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on December 9, 2009.

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on **December 9, 2009** before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai(Fort)/New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of ten-year tenure. The tenure of the Stock will commence on **December 9, 2009.**

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on **December 9, 2019 Rate of Interest**

Rate of Interest

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the stock sold at the auction. The interest will be paid on **June 9 and December 9.**

Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh
Sd/-
Principal Secretary.

Annexure-II

Revised scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities (Annex-II of the General Notification)

I. Objective

With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government securities, it is proposed to allow participation of eligible individuals and institutions on “non-competitive” basis in the auctions of State Government securities. Accordingly, non-competitive bids up to 10 percent of the notified amount will be accepted in the auctions of State Government securities. The reserved amount will be within the notified amount.

II. Eligibility

Participation on a non-competitive basis in the auctions of State Government Securities will be open to investors who satisfy the following:

- (i) do not maintain current account (CA) or Subsidiary General Ledger (SGL) account with the Reserve Bank of India.

Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks shall be covered under this scheme in view of their statutory obligations.

- (ii) make a singly bid for an amount not more than 1 percent of notified amount (face value) per auction.

- (iii) Submit their bid through any one bank or PD offering this scheme.

Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks that maintain SGL account and current account with the Reserve Bank of India shall be eligible to submit their non competitive bids directly.

III. Coverage

Subject to the conditions mentioned above, participation on “non competitive” basis is open to any person including firms, companies, corporate bodies, institutions, provident funds, trusts and any other entity as may be prescribed by RBI. The minimum amount for bidding will be Rs. 10,000 (face value) and thereafter in multiples in Rs. 10,000 as hitherto for investment in State Government securities.

IV. Other operational Guidelines.

1. It will not be mandatory for the retail investor to maintain a Gilt Account (under Constitution Subsidiary General Ledger(CSGL) facility) with the bank or PD through whom they wish to participate. However, an investor can make a single bid under this scheme. An undertaking to the effect that **the investor is making** only a singly bid will have to be obtained and kept on record by the Bank or PD.
2. Each Bank or PD on the basis of firm orders received from their constituents will submit a single consolidated non-competitive bid on behalf of all its constituents in electronic format on the Negotiated Dealing System (NDS) except in extraordinary circumstances such as general failure of NDS system, noncompetitive bid in physicals form will not be accepted.
3. Allotment under the non-competitive segment to the bank or PD will be at the weighted average rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The securities will be issued to the bank or PD against payment on the date of issue irrespective of whether the bank or PD has received payment from their clients.
4. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (i.e., 10 percent of notified amount), pro rata allotment would be made. In case of partial allotments, it will be the responsibility of the bank or PD to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.
5. In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to competitive portion of the notified amount.
6. Security would be issued only in SGL form by RBI. RBI would credit either the main SGL account or the CSGL account of the bank or PD as indicated by them. The facility for affording credit to the main SGL account is for the sole purpose of servicing investors who are not their constituents. Therefore, the bank or PD would have to indicate clearly at the time of tendering the noncompetitive bids the amounts (face value) to be credited to their SGL account and the CSGL account. Delivery in physical form from the main SGL account permissible at the instance of the investor subsequently.
7. It will be the responsibility of the bank or the PD to pass on the securities to their clients. Except in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the clients shall be completed within five working days from the date of issue.

8. The bank or PD can recover up to six paise per Rs. 100 as brokerage/commission/service charges for rendering this service to their clients. However, such costs may be recovered and accounted for separately from the clients and should not be built into the price. In case the transfer of securities is effected subsequent to the issue date of the security, the consideration amount payable by the client to the bank or PD would also include accrued interest from the date of issue.
9. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities, accrued interest wherever applicable and brokerage/commission/service charges may be worked out by the bank or PD as per agreement with the client. It may be noted that no other costs such as funding costs should be built into the price or recovered from the client.
10. Banks and PDs will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the Reserve Bank of India(Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the Bank.

V. Review of the Scheme

The foresaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered necessary, the Scheme will be modified in consultation with the State Governments.

